



'पहले चरण में ही टूटा टीएमसी का अहंकार', बंगाल में पीएम मोदी ने किया बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा

पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले चरण में वोटिंग के बाद साफ हो चुका है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करने जा रही है। 'मां रो रही हैं', 'माटी' सुमपैटियों के साथ; 'मानुष' डरा हुआ है', पीएम मोदी का ममता पर निशाना

"बंगाल में महा जंगलराज", पीएम मोदी ने टी२२ के कोलकाता प्रोशाग में अराजकता को लेकर ममता सरकार को घेरा (जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जारी है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में

विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं। पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले चरण में वोटिंग के बाद साफ हो चुका है कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करने जा रही है।

टीएमसी का अहंकार टूट गया- पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा, हूपहले चरण के मतदान में बंगाल ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में भाजपा की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां-माटी-मानुष की बातें करके सत्ता में आई थीं, लेकिन अब इनके मुंह से मां-माटी-मानुष ये शब्द

तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? ये टीएमसी वाले अगर मां-माटी-मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैटियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया।

पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के पास सब कुछ है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भरपूर है, इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर वन राज्य बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आँन को याद रखना है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के इस आँन पर देशवासियों ने अपना सर्वस्व न्योछवर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज बंगाल को आपके एक

वोट की जरूरत है। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी



दिलाएंगे। टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, हूटीएमसी के महाजंगलराज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें और बेटियाँ हैं। बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है। संदेशखाली

पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के महाजंगलराज में यहां से बेटियाँ लापता हो रही हैं, लेकिन यहां की

टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। उन्होंने कहा कि बेटियों की इन्हें कोई चिंता नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अब

और नहीं, 4 मई के बाद भाजपा की सरकार इन गुंडों का चुन-चुन कर हिसाब करेगी।

'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, जानकर राहत मिली...', वाशिंगटन होटल में फायरिंग पर बोले पीएम मोदी

(जीएनएस)। वाशिंगटन में हिल्टन होटल में हुई फायरिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फायरिंग के बाद ट्रंप के सुरक्षित रहने पर राहत भरी सांस ली है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस घटना की निंदा की है।

उन्होंने ट्रंप समेत सभी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की।

प्रधानमंत्री ने लिखा, 'ये जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सिक्कोरिटी ब्रीच के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मैं उनकी लगातार सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूँ। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। डिज़र के दौरान कई राउंड

फायरिंग बता दें कि हिल्टन होटल में 'व्हाइट हाउस कॉरिडोर डेडलिन' के दौरान एक संदिग्ध ने कई राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान बॉल्कन में ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस समेत दिग्गज कैबिनेट अधिकारी मौजूद थीं। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने सभी को होटल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना के बाद व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

'वर्दी का गौरव और सीएम का साथ', लखनऊ पुलिस लाइन में गूजी महिला आरक्षियों की शपथ, योगी सरकार की नीतियों को सराहा

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के अंतर्गत वर्ष 2025 बैच के पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद चयनित महिला आरक्षियों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और सरकार की नीतियों की सराहना की। रायबरेली की दीप्ति पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में महिला आरक्षी पद की शपथ लेना उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने

कहा कि सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। जो जिम्मेदारी मिली और प्रदेश की सेवा करने की अपील की। जौनपुर की प्रीति पटेल ने कहा कि योगी सरकार में महिलाओं को

कई गुना बढ़ गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में बढ़ा आत्मविश्वास आरक्षी के पद पर चयनित काजल सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग का हिस्सा बनकर बेहद अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और किसी से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। आरक्षी के पद पर चयनित आरती यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा का अवसर मिलना सम्मान की बात है और वह अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी।

समान अवसर मिल रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। गाजीपुर की श्रुति यादव ने कहा कि उन्हें देश और प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है, यह उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी से सभी चयनित आरक्षियों का उत्साह

है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगी। योगी सरकार में बढ़ा महिलाओं का मान-सम्मान चयनित पुलिस आरक्षी सुमन यादव ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार का यह कदम महिलाओं के मान-सम्मान को बढ़ाने वाला है। उन्होंने महिलाओं से आगे आकर देश

अखिलेश ने वह सरकार पर लगाया 'पीड़ित परिवार का बयान बदलाने' का आरोप, हाथरस केस से की तुलना

(जीएनएस)। गाजीपुर में गंगा नदी में 15 वर्षीय किशोरी का शव मिलने के मामले में सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार (26 अप्रैल) योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पर बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है और इस घटना को हाथरस कांड की पुनरावृत्ति बताया। अखिलेश यादव ने (पूर्व टिवटर) पर पीड़िता के पिता का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बयान बदलने से सच नहीं बदल जाता। उत्तर प्रदेश ने कभी इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा, जिनके राज में गरीब और बेवस पीड़ितों पर अपने बयान बदलने का दबाव डाला

जाता है। उन्होंने दावा किया कि जब SP का प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने गया था, तो उन पर पत्थर फेंके गए। एक

2020 के हाथरस गैंगरेप-हत्या कांड से की। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में हाशिए पर पड़े परिवारों के साथ अन्याय हुआ और 'दबंग तत्व' आरोपी थे। अखिलेश ने पूछा कि क्या दिखावटी कार्रवाई से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? पीड़िता के पिता का बयान: राजनीति से दूर रहना चाहते हैं 25 अप्रैल को लड़की के पिता ने पत्रकारों से साफ कहा था कि वे राजनीतिक फायदे के लिए किसी नेता के घर आने नहीं चाहते। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की मौत से बहुत दुखी हूँ। पुलिस ने मेरी शिकायत पर कार्रवाई की, मुख्य आरोपी गिरफ्तार है। मैं नहीं चाहता कि कोई नेता राजनीतिक अवसरवादिता के लिए आए।

'आप' ने राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए भेजी याचिका

(जीएनएस)। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी करके भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत सभी सांसदों की सदस्यता समाप्त करने के लिए राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को अपनी याचिका भेज दी है। रविवार को यह जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि संविधान के विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में विलय करने वाले सभी सांसदों की सदस्यता जानी तय है।

सतों सांसदों ने न सिर्फ "आप" गद्दारी की है, बल्कि पंजाब के लोगों, लोकतंत्र और संविधान के साथ धोखा किया है। तोड़फोड़ के खेल में भाजपा माहिर है। भाजपा पहले ईडी-सीबीआई से विपक्ष के नेताओं को डराती है और फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। सबकी सदस्यता निश्चित रूप से समाप्त होगी रविवार को "आप" मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर संजय सिंह ने कहा कि संविधान के ज्ञाताओं, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ कपिल

सिब्ल, पीडीटी आचार्य समेत तमाम लोगों ने यह साफ कर दिया है कि जिन सात लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में विलय करने का फैसला लिया है, उन सबकी सदस्यता निश्चित रूप से समाप्त होगी। शनिवार को मीडिया बातचीत में एनडीए के घटक दल से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता ने भी स्पष्ट कहा कि इन नेताओं की सदस्यता तो हर हाल में जाएगी। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को भेजी गई

याचिका संजय सिंह ने आगे कहा कि सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके और कपिल सिब्ल की राय लेकर मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति को एक याचिका भेजी है। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के नियमों के मुताबिक इन सातों सदस्यों की सदस्यता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैंने उपराष्ट्रपति (सभापति) महोदय से मांग की है कि वे इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करें और अपनी ओर से एक न्यायपूर्ण फैसला दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को समझाया नये उत्तर प्रदेश का मतलब, भरोसा देते हुए 17 फार्मा कंपनियों को दिया एलओसी

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक रफ्तार को गति देने के क्रम में रविवार को 17 फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) प्रदान किया। इनमें से अधिकांश कंपनियों ने बीते दिनों लखनऊ में हुए फार्मा कॉन्क्लेव में भाग लिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान करने के साथ निवेशकों को सफलतम निवेश की शुभकामना दी और कहा कि आज का दिन प्रदेश के औद्योगिक व स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश में सेफ्टी, स्टैबिलिटी व स्पीड की गारंटी है। प्रदेश अब ट्रस्ट व टाइमली डिलीवरी के लिए पहचाना जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उत्तर प्रदेश हर रिलायबल पॉलिसी पार्टनर के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नए भारत का दर्शन हो रहा है।

स्किल्ड/अनस्किल्ड युवाओं को रोजगार एवं डवलपमेंट में उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता



देश की अर्थव्यवस्था ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। हम 200 देशों को सस्ती व गुणवत्तापरक दवाइयों उपलब्ध करा रहे हैं। फार्मा कॉन्क्लेव ने ग्लोबल हेल्थटेक के मैप पर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आपका निवेश केवल फार्मा/मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास के साथ जुड़ा है। लगभग 2000 करोड़ का निवेश रिसर्च

करेगा। इस निवेश से उत्तर प्रदेश के 10 हजार से अधिक स्किल्ड/अनस्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है। यूपी में निवेश से नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। नौ वर्ष में सरकार की स्पष्ट नीति व साफ नीयत के कारण उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर देश का ग्रोथ इंजन बना है। यूपी का

जीएसडीपी बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गया है। यूपी बड़ा मार्केट, माहौल उद्योगों के अनुकूल उन्होंने निवेशकों से कहा कि यूपी बड़ा मार्केट है। यहां का माहौल उद्योगों के अनुकूल है। यहां पर्याप्त बैंकिंग है। यूपी में हर सेक्टर में कार्य करने वाला वर्कफोर्स उपलब्ध है। यहां का 56 फीसदी वर्कफोर्स युवा है। इन युवाओं को स्किल, इनोवेशन व टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 21 हजार से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था है। 2017 के पश्चात यूपी की सुदृढ़ कानून व्यवस्था से देश-दुनिया परिचित है। प्रदेश अब पॉलिसी पैरालिसिस से निकलकर पॉलिसी स्टैबिलिटी तक पहुंच गया है। यहां 34 से अधिक सेक्टरल पॉलिसी है। निवेश मित्र, निवेश सारथी, उद्यम मित्र उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण



गरवी गुजरात
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2002

Jio FIBER

Jio tv+

Jio Fiber

dailyhunt

eBaba

dishtv SMART+

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

सम्पादकीय

डगमगाया आप का राज्यसभा किला वजह रही राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का भाजपा में जाना

राघव का घातक वार और सात सांसदों की बगावत से डगमगाया 'आप' का राज्यसभा किला, भारतीय राजनीति का यह शुक्रवार आम आदमी पाटा के इतिहास में हमेशा एक ऐसे मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला नजर आता है। राघव का घातक वार और सात सांसदों की बगावत से डगमगाया 'आप' का राज्यसभा किला भारतीय राजनीति के फलक पर 2 अप्रैल 2026 को जो चिंगारी सुलगनी शुरू हुई थी, उसने 22 दिनों के भीतर एक ऐसी सियासी आग का रूप ले लिया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पाटा का राज्यसभा वाला किला लगभग ढह चुका है। यह महज वुछ सांसदों का दल-बदल नहीं है, बल्कि उस पाट से लोकेन राघव के विचारधारा की सामूहिक हत्या है, जिसके दम पर एक दशक पहले अन्ना आंदोलन की कोख से यह पाटा जन्मी थी। राज्यसभा में पाटा के डिप्टी लीडर रहे राघव चड्ढा की अगुवाई में सात सांसदों का एक साथ पाला बदलना दिल्ली से लेकर पूजा तक की सियासत में वो भूतप है, जिसकी रिवलर स्कैल पर तीव्रता आने वाले कई सालों तक महसूस की जाएगी। मैं घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ और मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना जैसे फेल्टमी लगने वाले राघव के संवादों ने शुक्रवार को तब हकीकत का जामा पहन लिया, जब उन्होंने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा का दामन थामने का आलन किया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए संभवतः सबसे बड़ा और संगठित विद्रोह है। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा उस दिन लिख दी गई थी जब राघव चड्ढा को अचानक राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हाथ धोना पड़ा था। पाटा ने अंदरूनी तौर पर उन पर निष्प्रियता और गतिविधियों से दूरी बनाने के आरोप मढ़े थे, लेकिन राघव के तेवर बता रहे थे कि वे किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस बगावत में संदीप पाठक का नाम शामिल होना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका है। पाठक वही शख्स हैं जिन्हें आप का चाणक्य कहा जाता था, जिन्होंने पंजाब की सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में सौंपी और पाटा को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने के लिए पर्दे के पीछे से संगठन की मशीनरी तैयार की। जब संगठन का वास्तुकार ही इमारत ढहाने पर आमदा हो जाए, तो नेतृत्व की विफलता पर सवाल उठाना लाजिमी है। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल की भूमिका ने इस आग में धी का काम किया है। बिभव कुमार मामले के बाद जिस तरह स्वाति को अपनी ही पाटा में अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ा, उन्होंने उसे अपनी निजी अदावत बना लिया। आज जब वे राघव के साथ सुर में सुर मिला रही हैं तो यह साफ है कि आप के भीतर महिलाओं के सम्मान और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर जो दावे किए जाते थे, उनकी कलाई खुल चुकी है। तकनीकी तौर पर देखें तो यह बगावत बहुत ही सघे हुए कानूनी दाव-पेच के साथ की गई है। राज्यसभा में आप के वुल 10 सांसद थे, जिसमें से 7 का एक साथ अलग होना दल-बदल विरोधी कानून (एन्टी डिफेक्शन लां) के तहत अयोग्यता की तलवार को जुं दकर देता है। दौतिहाई के बाद जिस राघव चड्ढा की उस रणनीतिक वुशलता को दर्शाती है, जिसका लोहा कभी खुद केजरीवाल मानते थे। राघव का यह कहना कि वे गलत पाटा में सही व्यक्ति थे, न केवल केजरीवाल के नेतृत्व पर सीधा प्रहार है, बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का सपना लेकर इस पाटा से जुड़े थे। जिस पाटा ने 15 साल तक संघर्ष किया, उसका इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरना यह बताता है कि सत्ता के गलियारों में पहुंचते ही आम और खास की लकीरें धुंधली पड़ गईं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेतृत्व और जेल से सरकार चलाने की जिन ने शायद उन नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया जो अब तक वफादारी का दम भर रहे थे। पंजाब की सियासत के लिहाज से यह घटनाक्रम किसी सुनामी से कम नहीं है। बागी होने वाले सात में से छह सांसद पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री भावत मान के लिए यह स्थिति बेहद अशहज है, क्योंकि राघव चड्ढा को कभी पंजाब सरकार का रिमोट कंट्रोल कहा जाता था। मान और चड्ढा के बीच का शीतयुद्ध जगजाहिर था, लेकिन अब यह आमने-सामने की जंग में बदल चुका है। भाजपा ने इन चेहरों को अपने पाले में कर न केवल राज्यसभा में अपनी ताकत 148 तक पहुंचा दी है, बल्कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी एक मजबूत बिसात बिछ दी है। भाजपा, जो पंजाब में लंबे समय से एक मजबूत सिख चेहरे और संगठन की तलाश में थी, उसे अब हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और विवमजीत सिंह साहनी जैसे रसुखदार लोगों का साथ मिल गया है। यह मिशन पंजाब की वो शुरूआत है जिसने अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को फिलहाल दिल्ली और पंजाब की सीमाओं में ही वैद कर दिया है। संजय सिंह और अन्य आप नेता इसे ऑपरेशन लोटस और वेंद्रीय एजेंसियों का डर बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल डर के दम पर इतने बड़े स्तर पर बगावत संभव है? अन्ना हजारे की उस टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें उन्होंने कहा कि जब स्वार्थ समाज और देश से ऊपर हो जाता है, तो संगठन टूट जाते हैं। यह केजरीवाल की उस कार्यशैली का भी परिणाम है जिसमें उन्होंने धीरे-धीरे उन सभी पुराने चेहरों को किनारे कर दिया जिन्होंने उनके साथ धूल फांकी थी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और अर राघव-संदीप की यह पेहरिस्त बताती है कि पाटा में असहमति के लिए कोई जगह नहीं बची है। स्वाति मालीवाल का यह आरोप कि उन्हें मुख्यमंत्री के घर पर पीटा गया और फिर उन्हें ही बदनाम करने की कोशिश की गई, पाटा की नैतिक साख पर वो धब्बा है जो शायद ही कभी धुल पाए। राज्यसभा सचिवालय में अब कानूनी लड़ाई शुरू होगी, सदस्यता रह करने की याचिकाएं डाली जाएंगी और मामला कोर्ट तक जाएगा। लेकिन राजनीति में जो धारणा (परसेप्शन) एक बार बन जाती है, उसे बदलना मुश्किल होता है। जनता के बीच अब यह संदेश जा चुका है कि जो पाटा दूसरों को ईमानदारी का सट्टिफिकेट बांटती थी, उसके अपने घर में ही भारी अविश्वास का माहौल है।

साकिब और वैभव जैसे सितारे तराशने वाले राबिन सिंह की कहानी, जब जुनून के आगे फीका पड़ा मेडिकल करियर

(जीएनएस)। बिहार क्रिकेट लंबे समय के बाद ऊपर आया है और एक साथ कई खिलाड़ी भारत को दिए हैं। इन सबसे बीच पर्दे के पीछे काम करने वाले राबिन सिंह ने अपने प्रदेश की प्रतिभाओं को तराशने में अहम भूमिका निभाई है, जिनके बारे में कम ही लोगों को पता होगा।

चिकित्सा की दुनिया में एक सम्मानजनक और स्थिर जीवन राबिन सिंह का इंतजार कर रहा था, उनको उसी फील्ड में जाना था। वह हैदराबाद में रहते थे, राबिन की नजरें मेडिकल की किताबों या अस्पताल की गलियारों के बजाय बिहार की उन धूल भरी पिचों पर टिकी थीं, जहां क्रिकेट संसाधनों के अभाव में भी केवल जिनके दम पर जिंदा था।

बिहार के क्रिकेट का इतिहास संघर्ष से भरा रहा है। एक समय था जब मुंबई और दिल्ली जैसी टीमें

अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने वाली मशीन बनी हुई थीं, वहीं बिहार प्रशासनिक उलझनों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण गुमनामी में खोया था।



महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज को भी अपनी पहचान बनाने के लिए बिहार से झारखंड का रुख करना पड़ा था। लगभग अठारह वर्षों तक बिहार ने राजजी टूर्नामें तक

टीएमसी के 'मांस-मछली प्रतिबंध' वाले दावों के बीच पीएम मोदी ने कालीबाड़ी के किए दर्शन, जहां चढ़ता है नॉनवेज प्रसाद

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक थंथानिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। अपनी अनेखी मांसाहारी भोग परंपरा के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर का दौरा राज्य में भोजन संस्कृति पर चल रही राजनीतिक बहस के बीच हुआ। पीएम मोदी ने उत्तर कोलकाता में अपने रोड शो से पूर्व रविवार को मंदिर के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल में मांसाहारी भोजन पर जारी राजनीतिक गरमागरमी के कारण यह यात्रा महत्वपूर्ण रही। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित तुणमूल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में आने पर राज्य की भोजन संस्कृति में हस्तक्षेप कर सकती है।

टीएमसी ने क्या किया था दावा?

ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान कौन है, जिसके मदरसे पर चला सीएम योगी का बुलडोजर?

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर के खलीलाबाद स्थित गोशत मंडी में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर कार्रवाई कथित अवैध मदरसे पर हुई। भारी पुलिस बल और कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के कथित अवैध मदरसे पर बुलडोजर चल पड़ा। 6 बुलडोजर, 2 पोकलैंड मशीनें और करीब 100 पुलिसकर्मी (30 महिला सिपाही समेत) मौके पर तैनात। दो बुलडोजर के ब्लेड टूट गए, एक मशीन खराब हो गई, फिर भी 3 पिलर गिर चुके हैं। अब 45 से ज्यादा पिलर बाकी। तीन मंजिला इमारत (640 वर्ग मीटर, 25 कमरे, 5 करोड़ की लागत) को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है।

यह मदरसा 'कुलियातुल बनातिर रजविया' नाम से जाना जाता था। 2024 में बंद होने से पहले यहां 400 बच्चे (ज्यादातर लड़कियां) पढ़ते थे। उट योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती का यह नया उदाहरण है। लेकिन सवाल उठता है कि ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान आखिर कौन हैं? पाकिस्तान से उसका कनेक्शन क्या? विदेशी फंडिंग का रैकेट कैसे चला? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं...

आजमगढ़ से ब्रिटेन तक का सफर शमसुल हुदा खान का जन्म 12 जुलाई 1984 को संतकबीरनगर जिले के देवरिया लाला गांव (दुधारा थाना) में हुआ। मूल रूप से आजमगढ़ का



टीएमसी नेताओं ने बिहार और गुजरात जैसे भाजपा-शासित राज्यों में त्योहारों के दौरान मछली व मांस की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों का हवाला दिया था। बनर्जी ने ऐसी नीतियों को बंगाल की सांस्कृतिक पहचान की समझ की कमी बताया। भाजपा बोली- हमारी सरकार नॉनवेज पर नहीं लगाएगी रोक

भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। प्रदेश अध्यक्ष साभिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने स्पष्ट किया कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध की कोई योजना नहीं, व लोगों को खान-पान संबंधी पसंदों का सम्मान किया जाएगा।

इस विवाद पर भाजपा नेता और नागालैंड के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने मांस खाते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा, "ममता दीदी, मैं भाजपा में हूँ और शौक से मांसाहारी हूँ" यह

जिसके मदरसे पर चला सीएम योगी का बुलडोजर? पाकिस्तान कनेक्शन-विदेशी फंडिंग

गाटा संख्या 154) पर बना। 640 वर्ग मीटर (करीब 7000 वर्ग फीट) सरकारी जमीन पर। नक्शा पास नहीं, मंजूरी नहीं। 2024 में गांव निवासी अब्दुल हकीम ने रजट कोर्ट में



रहे वाला। 2007 में वह ब्रिटेन चला गया। 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। लेकिन भारत से नाता नहीं टूटा।

वह 2007 से 2017 तक आजमगढ़ के 'दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम' में सहायक अध्यापक के पद पर था। ब्रिटेन में रहते हुए भी उसने 31 जुलाई 2017 तक सरकारी वेतन लिया - कुल 16 लाख रुपये से ज्यादा। अनियमित मेडिकल लीव, शफर (स्वीच्छक सेमिनर) और यहां तक कि जीपीएफ-पेंशन का फायदा भी लिया। ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद यह सब कैसे? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मिलीभगत का आरोप। करीब 5 महीने पहले मामले के सामने आने पर विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया, संयुक्त निदेशक निरूप सिंह, गाजियाबाद उच्च साहित्य निष्पन्न पाठ, बरेली के लालमन और अमेठी के प्रभात कुमार।

2017 में वह भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया। लेकिन परिवार खलीलाबाद में ही है कि पत्नी सकलैन खातून, बेटा तौसीफ रजा और बहू अशरीन। मौलाना खुद ब्रिटेन में रहता है, लेकिन भारत में मदरसों और NGO के जरिए सक्रिय था।

सरकारी जमीन पर 5 करोड़ का निर्माण

मदरसा खलीलाबाद (UP इंड्र'ड्रिग्री डै'टुंरिंर) तहसील के खलीलाबाद गांव (मोतीनगर मोहल्ला,

एमपी बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल? जिन्होंने केजरीवाल को नहीं दिया धोखा, आप टूट के बीच क्यों नहीं गए भाजपा में?

(जीएनएस)। आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों के एक साथ अलग होने की खबरों ने पंजाब की राजनीति को हिला दिया। अअद के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत के बीच एक ऐसा नाम निखरकर सामने आया है, जिसने सत्ता के लालच और दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल की।

जहां राघव चड्ढा की अगुवाई में पंजाब के 6 और दिल्ली की 1 सांसद (स्वाति मालीवाल) ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं

बाबा सीचेवाल आज राज्यसभा में पंजाब से 'आप' के इकलौते और वफादार सिपाही बनकर खड़े हैं। राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा सीचेवाल कौन हैं, क्यों उन्हें बाकी सांसदों की तरह सत्ता राजनीति को हिला दिया। अअद के इतिहास की सबसे बड़ी बगावत के बीच एक ऐसा नाम निखरकर सामने आया है, जिसने सत्ता के लालच और दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल की।

जहां राघव चड्ढा की अगुवाई में पंजाब के 6 और दिल्ली की 1 सांसद (स्वाति मालीवाल) ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं

मंदिर के शानदार इतिहास से अवात कराया और उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक सुना। क्या प्रार्थनाएं कीं, यह मुझे नहीं पता, किंतु विश्वास है कि उन्होंने देश के कल्याण के लिए ही कामना की होगी।" कोलकाता का कालीबाड़ी मंदिर में

भव तो की है अटूट श्रद्धा

थंथानिया कालीबाड़ी कोलकाता के सबसे प्राचीन व प्रतिष्ठित काली मंदिरों में से एक है। 1703 में स्थापित, इसका 300 से अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास है, जो शहर के वर्तमान स्वरूप से भी पुराना है। यहाँ माँ सिद्धेश्वरी की पूजा की जाती है, जिन्हें 'जाग्रत' देवी माना जाता है। मंदिर समिति के सदस्य पलाश घोष ने बताया हम मंदिर से जुड़ी नौवीं पीढ़ी हैं, यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।"

कालीबाड़ी में चढ़ता है मांसाहारी प्रसाद?

यह मंदिर देवी को मांसाहारी

आजमगढ़: धोखाधड़ी और आर्थिक गड़बड़ी

तीसरा केस: विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियां। पहले दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

मदरसा 2024 में पहली बार सील हुआ। मौलाना ने पास की बाउंड्री में दूसरा मदरसा खोल लिया। नवंबर 2025 में वह भी सील। एक मकान में गर्ल्स हॉस्टल की चलाता था - संतकबीरनगर, बरौली, आजमगढ़ समेत कई जिलों की लड़कियां रहती थीं।

Yogi Governa>fme>oft का संरक्ष खर: क्यों चला बुलडोजर? UP में CM योगी आदित्यनाथ सरकार अवैध निर्माण, विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथ पर जोरो टॉलरेंस बरत रही है। यह कार्रवाई सिर्फ एक मदरसे की नहीं - अवैध मदरसों, फर्जी फंडिंग और रैंडिकलाइजेशन के खिलाफ बड़ी मुहिम का हिस्सा है। प्रशासन का कहना है कि मदरसा 2024 से बंद था, लेकिन इमारत खड़ी रखकर फंडिंग का नेटवर्क चल रहा था।

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। PAC की दो कंपनियां तैनात। स्थानीय लोग चुपचाप देख रहे हैं। मदरसा कमेटी अब कोई कानूनी रास्ता नहीं चला पाई।

बड़े सवाल और मायने

विदेशी फंडिंग का खतरा: भारत में मदरसों में विदेशी पैसा आने से कट्टरपंथ फैलने का खतरा। एऊ-अउर की जांच में ऐसे कई नेटवर्क सामने आए हैं।

सरकारी सैलरी घोटाला: ब्रिटिश नागरिक सरकारी वेतन ले - यह सरकारी खजाने के साथ धोखा। 4 अधिकारियों का निलंबन सिर्फ शुरूआत।

पाकिस्तान कनेक्शन: दावत-ए-इस्लामी जैसे संगठनों से लिंक। भारत की सुरक्षा के लिए फंडिंग का विषय।

मदरसा सुधार: वह सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है। पाठ्यक्रम आधुनिक बनाने और फंडिंग की पारदर्शिता पर जोर।

यह मामला सिर्फ एक इमारत गिराने का नहीं। यह दिखाता है कि वड में अवैध निर्माण, फर्जी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर सरकार की नजर कितनी पैनी है। मौलाना ब्रिटेन में हैं, लेकिन उसका नेटवर्क भारत में था। एऊ-अउर की जांच आगे बढ़ रही है। परिवार अभी खलीलाबाद में है।

बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर साबित किया कि कानून के राज में कोई भी ऊपर नहीं। शमसुल हुदा खान का केस विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान लिंक और सरकारी धोखाधड़ी का मिसाल बन गया है। अब देखना होगा कि जांच में और कितने बड़े खुलासे होते हैं। क्या ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी? क्या मदरसा शिक्षा में बड़े सुधार आएंगे?

नहीं खेली। पटना या समस्तीपुर के मैदानों पर पसीना बहाने खुशी के लिए सपना देखना किसी जोखिम से कम नहीं था। या तो वे दूसरे राज्यों के लिए

नहीं खेली। पटना या समस्तीपुर के मैदानों पर पसीना बहाने खुशी के लिए सपना देखना किसी जोखिम से कम नहीं था। या तो वे दूसरे राज्यों के लिए

जित इसी अंधकार के बीच राबिन सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने मेधावी छात्र होने के रिकॉर्ड और मेडिकल की पढ़ाई को पीछे छोड़कर कोचिंग और स्काउटिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके पिता जो खुद एक प्रोफेसर थे, इस फैसले से बेहद आहत थे और उन्होंने लंबे समय तक राबिन से बात नहीं की। राबिन ने हैदराबाद में क्रिकेट की बारीकियां और वहां के सिस्टम को करीब से देखा था। उन्होंने समझा कि एक गली के क्रिकेटर और आईपीएल स्तर के बीच का फासला केवल पेशेवर कोचिंग और सही मार्गदर्शन का होता है।

अभावों के बीच उम्मीद की नई बुनियाद

2017 में जब वे एक पारिवारिक शादी के सिलसिले में बिहार आए, तो नियति ने उन्हें वहीं रोक लिया। बिहार

नहीं खेली। पटना या समस्तीपुर के मैदानों पर पसीना बहाने खुशी के लिए सपना देखना किसी जोखिम से कम नहीं था। या तो वे दूसरे राज्यों के लिए

नहीं खेली। पटना या समस्तीपुर के मैदानों पर पसीना बहाने खुशी के लिए सपना देखना किसी जोखिम से कम नहीं था। या तो वे दूसरे राज्यों के लिए

जित इसी अंधकार के बीच राबिन सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने मेधावी छात्र होने के रिकॉर्ड और मेडिकल की पढ़ाई को पीछे छोड़कर कोचिंग और स्काउटिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके पिता जो खुद एक प्रोफेसर थे, इस फैसले से बेहद आहत थे और उन्होंने लंबे समय तक राबिन से बात नहीं की। राबिन ने हैदराबाद में क्रिकेट की बारीकियां और वहां के सिस्टम को करीब से देखा था। उन्होंने समझा कि एक गली के क्रिकेटर और आईपीएल स्तर के बीच का फासला केवल पेशेवर कोचिंग और सही मार्गदर्शन का होता है।

अभावों के बीच उम्मीद की नई बुनियाद

2017 में जब वे एक पारिवारिक शादी के सिलसिले में बिहार आए, तो नियति ने उन्हें वहीं रोक लिया। बिहार

नहीं खेली। पटना या समस्तीपुर के मैदानों पर पसीना बहाने खुशी के लिए सपना देखना किसी जोखिम से कम नहीं था। या तो वे दूसरे राज्यों के लिए

जित इसी अंधकार के बीच राबिन सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने मेधावी छात्र होने के रिकॉर्ड और मेडिकल की पढ़ाई को पीछे छोड़कर कोचिंग और स्काउटिंग की दुनिया में कदम रखा। उनके पिता जो खुद एक प्रोफेसर थे, इस फैसले से बेहद आहत थे और उन्होंने लंबे समय तक राबिन से बात नहीं की। राबिन ने हैदराबाद में क्रिकेट की बारीकियां और वहां के सिस्टम को करीब से देखा था। उन्होंने समझा कि एक गली के क्रिकेटर और आईपीएल स्तर के बीच का फासला केवल पेशेवर कोचिंग और सही मार्गदर्शन का होता है।

अभावों के बीच उम्मीद की नई बुनियाद

2017 में जब वे एक पारिवारिक शादी के सिलसिले में बिहार आए, तो नियति ने उन्हें वहीं रोक लिया। बिहार

यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई, लखनऊ-बिजनौर समेत कई जिलों में 12 हजार पंजीकरण रद्द, जानें वजह

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण अभियान के तहत 'उम्मीद पोर्टल' पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दस्तावेजों में कमी और गलत जानकारी के कारण राज्य के 12,000 से अधिक वक्फ संस्थानों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें लखनऊ और बिजनौर जिले सबसे आगे हैं। प्रभावित संस्थानों को अपनी गलतियां सुधारकर 5 जून तक दोबारा आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है, ताकि संपत्तियों का पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के 'उम्मीद पोर्टल' पर चल रहे सत्यापन कार्य के दौरान यूपी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य भर में अब तक 12 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण खारिज कर दिए गए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की इस प्रक्रिया में लखनऊ और बिजनौर जैसे जिले सबसे ऊपर हैं, जहां भारी संख्या में खामियां पाई गई हैं।

क्यों रद्द हुए 12 हजार पंजीकरण ?

जांच में सामने आया है कि पंजीकरण रद्द होने की मुख्य वजह

कार्रवाई की जद में आए हैं। लखनऊ और बिजनौर में



डेटा एंट्री में गलतियां और अचूरे दस्तावेज हैं। कई संस्थानों ने पोर्टल पर जानकारी तो दी, लेकिन उसके समर्थन में जरूरी कानूनी कागजात अपलोड नहीं किए, निरस्त की गईं इन संपत्तियों में छोटी मस्जिदों की जमीन से लेकर 300 एकड़ तक के बड़े कब्रिस्तान शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा गाज कब्रिस्तानों के पंजीकरण पर गिरी हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मस्जिदें हैं। इनके अलावा मदरसे, ईदगाह, इमामबाड़ा और दरगाह भी इस

सबसे बुरा हाल पंजीकरण निरस्त होने के मामले में राजधानी लखनऊ पहले पायदान पर है, जहां 1,114 वक्फ संपत्तियों के आवेदन मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके ठीक बाद बिजनौर का नंबर आता है, जहां 1,003 आवेदन खारिज किए गए हैं। अन्य जिलों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है: सहारनपुर: 990 मामले रद्द बाराबंकी: 577 मामले रद्द अमरोहा: 85 मामले रद्द बागपत: 60 मामले रद्द बरेली: 17 मामले रद्द

सुधार के लिए मिला अंतिम मौका

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई स्थायी नहीं है, बल्कि सुधार का एक मौका है। जिन संस्थानों के पंजीकरण खारिज हुए हैं, वे 5 जून तक सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर फाइनल डेटा अपलोड करने की आखिरी तारीख 6 जून तय की गई है। इसके बाद किसी भी चूक के लिए संस्थान खुद जिम्मेदार होंगे।

क्या है 'उम्मीद पोर्टल' और इसका उद्देश्य ?

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जून में 'उम्मीद पोर्टल' की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का एक ऐसा डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और संपत्तियों का प्रबंधन आसान हो सके। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन करीब 1.26 लाख संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनका अब पूर्ण डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इससे न केवल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि उनकी आय और उपयोग में भी पारदर्शिता आएगी।

मोजतबा खामेनेई की भी हो चुकी है मौत ? पोस्टर में 'शहीद' की तरह दिखाई तस्वीर

(जीएनएस)। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे, मोजतबा खामेनेई को लेकर इन दिनों रहस्य गहरा गया है। हाल ही में शहीदों को समर्पित एक आधिकारिक कार्यक्रम में उनकी तस्वीर प्रदर्शित की गई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

आमतौर पर ऐसी जगहों पर केवल दिवंगत शहीदों की तस्वीरें ही लगाई जाती हैं, जिससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मोजतबा के साथ कोई अनहोनी हुई है। उनकी लंबे समय से सार्वजनिक अनुपस्थिति और इजराइली या अमेरिकी हमलों से जुड़ी अप्रुखबरें इस संस्येस को और बढ़ा रही हैं।

मोजतबा खामेनेई की तस्वीर पर छिड़ा विवाद

ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (वक्फ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मोजतबा खामेनेई का पोस्टर उन लोगों के साथ लगाया गया जिन्हें 'शहीद' माना जाता है। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में

खलबली मचा दी है। जानकारों का कहना है कि ईरान में प्रोटोकॉल बहुत सख्त हैं; ऐसे में जीवित व्यक्ति की

तस्वीर शहीदों के बीच दिखना या तो बहुत बड़ी गलती है या फिर किसी बड़ी सच्चाई को छिपाने की कोशिश। अभी तक सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

घायल होने की खबरें और रहस्यमयी चुप्पी

सोशल मीडिया और कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोजतबा हालिया सैन्य हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ सूत्रों

के अनुसार, उनके चेहरे पर चोटें आई हैं और वे बोलने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, इन दावों की कोई

तस्वीर शहीदों के बीच दिखना या तो बहुत बड़ी गलती है या फिर किसी बड़ी सच्चाई को छिपाने की कोशिश। अभी तक सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

हर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका को चेतावनी

ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'हर्मुज स्ट्रेट' पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की बात कही है। खतम अल-अंबिया मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका या उसके सहयोगियों ने समुद्री नाकेबंदी की कोशिश की, तो ईरान कड़ा जवाब देगा। ईरान का मानना है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव कम हो रहा है और उसे अंततः पीछे हटना पड़ेगा। मोजतबा को लेकर चल रहे संस्येस के बीच ईरान अपनी सैन्य ताकत के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है।

क्या ट्रंप ने खुद करवाई फायरिंग? प्रेस सचिव के 'फायर शाट' वाले बयान से गहराया शक

(जीएनएस)। अमेरिका के वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां लोग डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनने के लिए उत्साहित थे, वहां अचानक गोलियों की आवाज गुंजने लगी। इस हमले ने राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इसी बीच ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मजाक में 'फायर-शाट' की बात कही थी, जो हकीकत में बदल गई। कैरोलिन लेविट का वायरल वीडियो

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने घटना से ठीक पहले फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने दर्शकों से ट्रंप का भाषण सुनने की अपील की थी। लेविट ने मजाकिया लहजे में कहा था कि ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह धमाकेदार होगा और भाषण

के दौरान कुछ 'फायर-शाट' (तीखे हमले) देखने को मिलेंगे। उस समय उनके इस बयान को केवल राजनीतिक तंज माना गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां सचमुच गोलियां चल गईं।

होटल में हमले का

अनुसार, हमलावर के पास शांटेन थी और उसने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली भी चलाई। सुरक्षा जैकेट की वजह से एजेंट की जान बच गई। अचानक हुई इस गोलीबारी से पूरे हॉल में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए टेबल

के नीचे छिपने लगे। सीक्रेट सर्विस की त्वरित कार्रवाई गोली चलते ही यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड



खौफनाक संजर्

वाशिंगटन हिल्टन होटल में पत्रकारों का डिनर शुरू होने ही वाला था कि तभी एक हथियारबंद हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के

लखनऊ: 986 महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड, आधुनिक पुलिसिंग प्रशिक्षण का प्रदर्शन

(जीएनएस)। लखनऊ में 986 महिला रिक्त आरक्षियों की दीक्षांत परेड 26 अप्रैल को होगी, जिसमें सीएम योगी सलामी लेंगे और साइबर क्राइम सहित आधुनिक पुलिसिंग प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जाएगा।

आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-2025 के तहत चयनित 60,244 आरक्षियों में से पुलिस कमिश्नर लखनऊ की आरटीसी में प्रशिक्षण प्राप्त 986 महिला रिक्त आरक्षियों की दीक्षांत परेड 26 अप्रैल को रिजर्व पुलिस लाईंस, महानगर, लखनऊ में आयोजित होगी। परेड का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलामी लेंगे, प्रशिक्षण के दौरान इन महिला आरक्षियों को आधुनिक पुलिसिंग से लेकर साइबर क्राइम तक का प्रशिक्षण दिया गया है।

कार्यक्रम सुबह करीब 8 बजे शुरू होगा और इसे प्रदेश के सभी जनपदों के पुलिस लाईंस, पीएसी वाहिनियों व प्रशिक्षण संस्थानों में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इससे

एक साथ पूरे प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी मजबूत संदेश जाएगा।



2017 के बाद महिलाओं की रिकॉर्ड भर्ती

1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10 हजार महिलाओं की भर्ती हुई थी, जबकि 2017 के बाद यह संख्या 44 से 45 हजार पहुंच गई है। अब प्रदेश में पुलिस भर्ती होने पर 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती को

अनिवार्य कर दिया गया है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ पुलिसिंग प्रशिक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती-



2025 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं महिला आरक्षियों को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ आधुनिक पुलिसिंग के सभी जरूरी पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षण में सोशल पुलिसिंग, साइबर क्राइम की रोकथाम, आधुनिक तकनीक, सीसीटीवीएनएस,

फॉरेंसिक साइंस व मेडिसिन, हथियार संचालन, अपराध नियंत्रण, विवेचना, पुलिस अभियोजन, सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और पुलिस रेडियो संचार प्रणाली जैसे विषय शामिल रहे।

आधुनिक, संवेदनशील और सक्षम पुलिस कर्मी के रूप में किया गया तैयार

इसके साथ ही भारतीय संविधान, मानवाधिकार, लैंगिक संवेदनशीलता, पुलिस का कार्यप्रणाली, अनुशासन, नैतिकता और जवाबदेही पर भी विशेष जोर दिया गया।

व्यावहारिक प्रशिक्षण के तहत आरक्षियों को गार्ड ड्यूटी, बंदी एस्कॉर्ट, हवालात ड्यूटी, वर्दी पहनने के नियम, अधिकारियों की वर्दी पहचान, सैल्यूट की विधि, योग, खेल और श्रमदान जैसे गतिविधियों में भी दक्ष बनाया गया। यह प्रशिक्षण महिला आरक्षियों को आधुनिक, संवेदनशील और सक्षम पुलिस कर्मी के रूप में तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बालेन सरकार का चीन को बड़ा झटका, डैंगन के साथ हुए कई समझौतों की जांच के आदेश

(जीएनएस)। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही चीन के साथ हुए पिछले आर्थिक समझौतों पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के थिंक टैंक 'कलफ्रं' के अनुसार, चीन ने आर्थिक मदद के बहाने नेपाल की राजनीति और आंतरिक निर्णयों में हस्तक्षेप बढ़ाया है।

पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के कार्यकाल में हुए कई बड़े समझौतों को अब शक की निगाह से देखा जा रहा है। नई सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक पुरानी अटकी हुई परियोजनाओं की जांच पूरी नहीं होती, चीन के साथ कोई नया समझौता नहीं किया जाएगा।

ओली सरकार के फैसलों पर सवाल

के.पी. शर्मा ओली के कार्यकाल (2016-2018) के दौरान नेपाल ने चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) में शामिल होकर कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय इन्हें नेपाल की आर्थिक आजादी के लिए क्रांतिकारी बताया

गया था। हालांकि, अब यह आरोप लग रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे कोई ठोस वित्तीय योजना नहीं थी। नई सरकार यह जांच कर रही है कि आखिर क्यों ये समझौते केवल कागजों तक सीमित रह गए और इनका लाभ नेपाल की जनता को क्यों नहीं मिला।



अटकी हुई प्रमुख परियोजनाएं नेपाल में चीन की कई बड़ी योजनाएं सालों से टप पड़ी हैं। इनमें बूढ़ी गंडकी जलविद्युत परियोजना सबसे प्रमुख है, जिसका टेका कई बार रद्द और बहाल हुआ, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। इसी तरह, काठमांडू

को चीन से जोड़ने वाली केरंग-काठमांडू रेलवे भी तकनीकी और वित्तीय कारणों से 2026 तक अटकी हुई है। ट्रांस-हिमालयी कनेक्टिविटी नेटवर्क और सीमा पार बिजली लाइनों जैसे प्रोजेक्ट्स भी सिर्फ चर्चा का विषय बनकर रह गए हैं, जिससे

नेपाल के विकास को धक्का लगा है। डिजिटल और सुरक्षा संबंधी चिंताएं आर्थिक प्रोजेक्ट्स के अलावा, चीन की टेक कंपनियों जैसे हुवावे और 'व्प' द्वारा नेपाल में किए जा रहे डिजिटल विस्तार ने भी नई सरकार

को चिंता बढ़ा दी है। 2017 से शुरू हुए इन प्रयासों की गति बहुत धीमी है और इनके रणनीतिक प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल बुनियादी ढांचे में चीनी हस्तक्षेप से नेपाल की डेटा सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा हो सकता है, यही कारण है कि इन प्रोजेक्ट्स को भी गहन समीक्षा की जा रही है।

नई सरकार का कड़ा रुख

नेपाल की वर्तमान सरकार अब चीन के साथ अपने संबंधों में सावधानी बरत रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि परियोजनाओं में देरी और पारदर्शिता की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रसुवागढ़ी सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्तरी राजमार्गों की अधूरी स्थिति ने बीजिंग को नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। जब तक इन पुरानी परियोजनाओं में प्रगति नहीं होती और इनकी वित्तीय पारदर्शिता स्पष्ट नहीं होती, तब तक नेपाल चीन के साथ किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान फिर बने ठगों के शिकार, इस बार कैसे हो गया ₹87000 का स्कैम ?

(जीएनएस)। अभिनेता अर्चना पूरन सिंह और पति परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी हाल ही में ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गए। उनके क्रेडिट कार्ड से बिना अनुमति के 87,000 रुपये कट गए।

यह घटना उनके बड़े भाई आर्यमन सेठी के यूट्यूब चैनल 'आर्य व्लॉग्स' पर एक व्लॉग में सामने आई, जहां पूरा परिवार इस मामले पर खुलकर बात करता दिखा। शुरू में तो चिंता और परेशानी छाई रही, लेकिन बाद में हंसी-मजाक के साथ परिवार ने इस स्कैम को हँडल कर लिया...

व्लॉग में क्या हुआ ? पूरा किस्सा

आर्यमन के व्लॉग में आयुष्मान काफी परेशान नजर आए। उन्होंने बताया, 'मेरे क्रेडिट कार्ड से 87,000 रुपये निकाल लिए गए।' यह सुनते ही मां अर्चना पूरन सिंह ने तुरंत सलाह दी, 'इसे रद्द कर दो। क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करो।' आयुष्मान ने स्थिति समझाई, 'उन्होंने सात दिन के मुफ्त ट्रायल के बहाने पूरे साल का पैसा ले लिया।' अर्चना आश्चर्य से बोलीं, '87,000 रुपये?' और फिर दोबारा कार्ड रद्द करने की सलाह दी। पिता परमीत सेठी (डॉ॰ रीड) ने शांति बनाए रखते हुए कहा, 'कार्ड रद्द न करें, भुगतान रद्द करें।' लेकिन आयुष्मान अभी भी कन्फ्यूज थे और पूछ बैठे, 'मुझे वह विकल्प कहाँ मिलेगा?' इस पर पूरा परिवार हंस पड़ा। आर्यमन ने मजाक में छोटे भाई से कहा, 'तुम मम्मी-पापा से ये पैसे नहीं ले

सकते।' अर्चना ने हंसते हुए याद दिलाया, 'ये तुम्हारे ही पैसे हैं।' आयुष्मान ने बचाव में कहा, 'मैंने ये पापा के लिए किया!' परमीत हंस पड़े, लेकिन अर्चना ने तंज करवा, 'वो तुमसे पैसे ले लेंगे। तो तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो?' परमीत ने कहा, 'मैं खुश नहीं

हूँ, मैं बस यह सोच रहा हूँ कि वह इस बात को लेकर कितना घबरा रहा है।' पुरानी याद ताजा हो गई

आर्यमन ने व्लॉग में एक पुरानी घटना भी याद की। उन्होंने बताया, 'जब हम मेरे गाने 'छोटी बातों' के लिए रेकी कर रहे थे, तब आयुष्मान को मैसेज आया कि उनके प्लेस्टेशन खाते से 80,000 रुपये डेबिट हो गए। वो पैसे कभी वापस नहीं मिले।' आयुष्मान का बचाव और परिवार की हंसी

पूरे साल का चार्ज एक साथ काट लिया। पहले 0 डॉलर का ट्रांजेक्शन हुआ, जिसे मैंने अप्रूव कर दिया। एक घंटे बाद 87,000 रुपये कट गए।

परमीत ने कहा, 'तुम हमेशा जल्दी में रहते हो।' आयुष्मान ने विरोध जताया, 'मैं जल्दी में नहीं था। मैं तुम्हारा

हेल्प सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करो।'

आयुष्मान ने माना कि करीब एक साल पहले भी उनके साथ ऐसी ही धोखाधड़ी हुई थी, लेकिन उस वक्त पैसे वापस मिल गए थे। योगिता (शायद परिवार की कोई सदस्य) ने मजाक में कहा, 'इसका मतलब है कि आप धोखाधड़ी करने वालों के नियमित ग्राहक हैं।' परमीत ने अंत में गंभीरता से कहा, 'इस बार ऐसा नहीं है। आपने बटन दबाया और उन्हें पैसे काटने की अनुमति दी।'

क्या सीख मिली ?

यह स्कैम फ्री ट्रायल के नाम पर आम हो रही ऑनलाइन ठगी का एक और उदाहरण है। आयुष्मान जैसे युवा अक्सर जल्दबाजी में छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर देते हैं, जिसका फायदा स्कैमर्स उठा लेते हैं। परिवार ने इस घटना को हल्के-फुल्के अंदाज में शेयर किया, ताकि लोग सतर्क रहें। आर्यमन के व्लॉग ने दिखाया कि सेलिब्रिटी परिवार भी इन स्कैम से अछूते नहीं हैं। बैंक से तुरंत संपर्क करें, कार्ड ब्लॉक करें और जरूरी दस्तावेज रखें-ये छोटी-छोटी सावधानियां भारी नुकसान से बचा सकती हैं। 87,000 रुपये गए, लेकिन परिवार की हंसी और एकजुटता ने इस स्कैम को यादगार बना दिया। आयुष्मान अब खुद इसे सुलझाई की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपने कभी ऐसा स्कैम फेस किया ? कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें।

